



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2003/15 आश्विन, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 11 सितम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (3) 1/1994-लूज-13009-13218.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०-एच०ए०(3) 1/94-19181-362, तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश तारीख 25 नवम्बर, 1997 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और जिसे इनके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया जाता है।

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसके प्रस्तावित संशोधनों हेतु कोई आक्षेप/मुद्दाव हों, तो वह उसे, प्रस्तावित संशोधनों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन को तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विशेष सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार, एस० डी० ए० कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सकेगा।

उपर नियत अवधि के भीतर प्राप्त किए गए आक्षेप (आक्षेपों), या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2003 है।

2. नियम 42 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 42 में,—

(क) उप-नियम (1) में “यूवा मण्डल” शब्दों के पश्चात् “सम्बद्ध विभाग” चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-नियम (3) में “उत्पादन समिति” शब्दों के स्थान पर “खाद्य नागरिक आपूर्ति और उप-भोक्ता समिति” शब्द तथा चिन्ह रखे जायेंगे।

(ग) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (3-क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3-क). धारा 23 की उप-धारा (3) के अधीन ग्राम सभा के सदस्यों में से सहयोजित किए जाने वाले सदस्य, ग्राम सभा द्वारा बहुमत द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाएंगे।”।

(घ) उप-नियम (6) में “ग्राम पंचायत का सचिव” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, ग्राम पंचायत का सचिव या पंचायत सहायक” शब्द और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) उप-नियम (10) में “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “अठ्ठाई वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

3. नियम 73 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 73 में चिन्ह और शब्दों “1 फीस सभा निधि में जमा की जाएगी और समन या नोटिस की तामील करने वाले व्यक्ति को तीन रुपये प्रति समन या नोटिस की दर से दिया जाएगा” के स्थान पर “और समन या नोटिस की तामील करने वाले व्यक्ति को संदत की जाएगी” शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (3)1/1994-loose dated 11th September, 2003 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 11th September, 2003

No. PCH-HA (3) 1/1994 (Loose)-13009-13218.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994),

the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 25th November, 1997 *vide* Government Notification number, PCH-HA (3) 1/94-19181-362 dated the 25th November, 1997 and the same are hereby published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra-ordinary), for the information of the persons likely to be affected thereby.

Any interested person who has any objection(s)/suggestions(s) to the proposed amendments, may send the same to the Special Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of thirty days from the date of publication of the proposed amendments in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these rules, namely :—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2003.

2. *Amendment of rule 42.*—In rule 42 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 (hereinafter called the “said rules”),—

- (a) In sub-rule (1) after the words “Yuvak Mandals”, the sign and words “the concerned Departments” shall be inserted ;
- (b) In sub-rule (3) for the words “Production Committee”, the words and sign “Food, Civil Supply and Consumer Committee” shall be substituted;
- (c) After sub-rule (3), the following sub-rule (3-A) shall be inserted, namely :—
“(3-A). Members to be co-opted from amongst the members of the Gram Sabha under sub-section (3) of section 23 shall be nominated by the Gram Sabha by majority.”;
- (d) In sub-rule (6), after the words “Gram Panchayat”, the words and signs “the Panchayat Sahayak as the case may be” shall be inserted; and
- (e) In sub-rule (10) for the words “one year”, the words “two and a half years” shall be substituted.

3. *Amendment of rule 73.*—In rule 73 of the said rules, for the sign and words “The fee shall be credited to the Sabha Fund and may be paid to the person serving the summons or notices at the rate of rupees three per summon or notice”, the words “and shall be paid to the person serving the summons or notices” shall be substituted.

By order,

Sd-
Secretary.

